छत्तीसगढ़ की तृतीय विधान सभा
षष्ठम सत्र

श्री शेखर दत्त

राज्यपाल, छत्तीसगढ़

का

अभिभाषण

दिनांक 17 फरवरी, 2011

माननीय सदस्यगण,

नए दशक के पहले वर्ष 2011 में छत्तीसगढ़ विधान सभा के पहले अधिवेशन के अवसर पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं । नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ की स्थापना के दस वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इन दस वर्षो में छत्तीसगढ़ राज्य ने जो अभूतपूर्व प्रगति की है, उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं । इसके साथ ही विकास का एक नया सफर भी शुरू हुआ है। यह नया सफर छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में नए गौरवशाली अध्याय रचे, इसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं ।

2. मेरी सरकार ने राज्य में निरंतर विकास के प्रयास किए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ में विगत पांच वर्षो की औसत विकास दर 10.89 प्रतिशत रही है, जो राष्ट्रीय औसत 8.49 प्रतिशत से अधिक है । विगत वर्ष 2009–10 में छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भी देश में सबसे अधिक 11.49 प्रतिशत रही । इसी तरह प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर में भी छत्तीसगढ़ देश के अन्य सभी राज्यों से आगे रहा है । यह राज्य के सभी क्षेत्रों में हो रही प्रगति का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है ।

3. मेरी सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है । राज्य की प्रमुख फसल धान पर किसानों की निर्भरता को देखते हुए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की उत्तम व्यवस्था की गई है, जिसके कारण विगत वर्ष 44.27 लाख टन से अधिक धान खरीदी की गई और किसानों को लगभग चार हजार 700 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया । उम्मीद है कि बीते वर्ष का कीर्तिमान भी टूटेगा और 50 लाख टन से अधिक धान उपार्जन का नया कीर्तिमान इस वर्ष बनेगा ।

4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली मध्यम और गरीब तबकों के जीवन का एक बड़ा सहारा होती है। इसलिए मेरी सरकार ने निरंतर सुधार करते हुए देश का सर्वश्रेष्ठ पीडीएस विकसित किया है। पीडीएस में नवाचार की मुहिम जारी रखते हुए अब इसमें 'स्मार्ट कार्ड' का उपयोग शुरू किया जा रहा है। पायलेट प्रोजेक्ट के तहत रायपुर शहर में खाद्यान्न का वितरण स्मार्ट कार्ड से करने की तैयारी की जा रही है।

5. एक रूपए एवं दो रूपए किलो चावल प्रदाय करने वाली योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिले, इस दिशा में बरती गई सावधानी के कारण बोगस राशन कार्ड समाप्त करने हेतु कड़ें कदम उठाए गए हैं। पीडीएस से पौष्टिक आहार देने की नई शुरूआत भी की जा रही है, जिसके तहत रियायती दरों पर चना प्रदान किया जाएगा। इस योजना की शुरूआत बस्तर संभाग से की जा रही है।

6. किसानों को देश में सबसे कम ब्याज दर 3 प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध कराने की शुरूआत मेरी सरकार ने की थी । इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अब कृषि से संबद्ध पशुपालन, मछलीपालन और उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए भी न सिर्फ इसी न्यूनतम दर पर ऋण दिया जा रहा है बल्कि ऋण सीमा भी एक

लाख रूपए तक बढ़ा दी गई है । किसानों की सुविधा के लिए उन्हें सहकारी बैकों तथा समितियों से करीब 10 लाख 47 हजार क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं ।

7. मेरी सरकार ने फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी में सुधार, मानक बीजों का उपयोग, सिंचाई, खाद, कृषि उपकरण जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया है। 'अक्ति बीज संवर्धन योजना' के अंतर्गत मानक बीजों के उपयोग तथा उत्पादन में जोर देने से विगत दो वर्षों में करीब 250 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। 'हरित क्रांति विस्तार योजना' के अंतर्गत वर्षा–जल के संरक्षण और कृषि कार्य में उपयोग हेतु 58.20 करोड़ रूपए की लागत से सिंचाई तालाब और चेक–डेम बनाए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुई भरपाई के लिए बीमा कंपनियों से लगभग 124 करोड़ रूपए के दावों का भुगतान करीब तीन लाख 62 हजार किसानों को कराया गया। सिंचाई जल के बेहतर उपयोग हेतु दिए जा रहे अनुदान के कारण लगभग 84 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर तथा ड्रिप सिस्टम लगाये जा चुके हैं । कृषि यांत्रिकीकरण हेतु किसानों को केन्द्र द्वारा दिए जा रहे 25 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा भी 25 प्रतिशत का विशेष अनुदान दिया जा रहा है । लगातार प्रयासों से उद्यानिकी फसलों का रकबा अब बढ़कर करीब पांच लाख 40 हजार हेक्टेयर हो गया है । पशुधन विकास एवं गौ–वंश के संवर्धन हेतु 'कामधेनु विश्वविद्यालय' स्थापना की पहल की जा रही है ।

8. श्रम कल्याण गतिविधियों के विस्तार हेतु कवर्धा, कांकेर और कोरिया जिलों में नए श्रम पदाधिकारी कार्यालय खोले जा रहे हैं । राज्य के असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए 'छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल' तथा 'छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल' का गठन किया गया है । केन्द्र एवं राज्य की विभिन्न योजनाओं का लाभ श्रमिकों को देने के लिए मेरी सरकार हर संभव कदम उठा रही है ।

9. मेरी सरकार ने सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए न सिर्फ नई योजनाएं बनाई है बल्कि बरसों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने पर भी जोर दिया है । घुमरिया बैराज, सूखानाला बैराज, कर्रानाला बैराज, मध्यम परियोजनाएं तथा केलो वृहद योजना के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है, जिनके पूर्ण होने से लगभग 40 हजार 370 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी । मिनी माता बांगो परियोजना, खारंग, तांदुला जलाशय की नहरों की लाइनिंग का कार्य भी प्रगति पर है ।

10. राष्ट्रीय मापदण्ड के अनुसार 40 लीटर पेयजल प्रतिव्यक्ति, प्रतिदिन के मान से उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण अंचलों में दो लाख 10 हजार से अधिक हैण्डपम्प स्थपित किए जा चुके हैं । 72 हजार 329 बसाहटों में शुद्ध पेयजल का इंतजाम किया गया है । आगामी तीस वर्षों की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 60 नगरीय निकायों में नल–जल योजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी हैं । शेष निकायों में कार्य प्रगति पर हैं । इस वर्ष 172 ग्राम पंचायतों को 'निर्मल ग्राम' चुना गया है, जिसे मिलाकर प्रदेश में कुल 693 निर्मल ग्राम हो जाएंगे ।

11. मेरी सरकार ने राज्य में जन स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन हेतु 'स्वस्थ परिवर–समृद्ध प्रदेश' अभियान शुरू किया है । राज्य में 26 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 300 नए उपस्वास्थ्य केन्द्र और चार नए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस तरह संस्थाओं की संख्या के हिसाब से छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय मानक की बराबरी कर ली है। जन–सामान्य को विभिन्न पद्धतियों की चिकित्सा एक साथ दिलाने हेतु 15 जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुष विंग प्रारम्भ किया गया है। राज्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर नवीन योजनाएं लागू करने का सिलसिला जारी है। '108 संजीवनी एक्सप्रेस' की सेवाएं रायपुर एवं जगदलपुर में प्रारम्भ कर दी गई हैं, जिसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा। मरीजों को आपात स्थिति में तुरंत मदद के लिए यह सुविधा एक वरदान साबित होगी ।

12. संजीवनी कोष, बाल हृदय सुरक्षा, बाल श्रवण, महतारी–लइका स्वास्थ्य दिवस, सियान, ई–महतारी, विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला, पोषण पुनर्वास केन्द्र आदि योजनाओं से बीपीएल परिवारों सहित समाज के हर तबके को लाभ मिला है । 'जननी सुरक्षा योजना' के सफल अमल से संस्थागत प्रसव को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत तक लाने में सफलता मिली है । 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' के तहत 10 लाख 40 हजार परिवारों को 'स्मार्ट कार्ड' जारी किए जा चुके हैं, शेष सभी बीपीएल परिवारों को वर्ष 2011–12 में स्मार्ट कार्ड पदान करने का लक्ष्य है ताकि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को सभी गरीबों की पहुंच में लाया जा सके ।

13. मेरी सरकार ने स्कूली शिक्षा को प्रभावकारी बनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ कदम से कदम मिलाया है ताकि राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सके । प्रारंभिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण तथा माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संचालित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई है । बेहतर अधोसंरचना विकसित करने के कारण शालाओं में दर्ज संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है । राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है । इस वर्ष 319 नए प्राथमिक विद्यालय, 85 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 218 हाईस्कूल तथा 95 हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले गए हैं । प्राथमिक शाला के लिए 319 भवन तथा तीन हजार 680 अतिरिक्त कमरे, उच्च प्राथमिक शाला के लिये 85 भवन तथा एक हजार 823 अतिरक्त कमरे, हाईस्कूल के 218 भवन एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के लिए 60 भवन बनाने का कार्य प्रगति पर है । इसके अलावा 72 मॉडल स्कूलों और 74 कन्या छात्रावासों की भी मंजूरी दी गई है ।

14. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों तथा युवाओं को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें शिक्षण–प्रशिक्षण की बेहतर सुविधाएं देने के भी अच्छे परिणाम मिले हैं । स्वस्थ तन–स्वस्थ मन योजना, विशेष शिक्षण केन्द्र योजना, राज्य छात्रवृत्ति योजना, भोजन सहाय योजना, आगमन भत्ता योजना, विशेष कोचिंग योजना, आश्रम शाला योजना, छात्रावास योजना, गणवेश प्रदाय योजना, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, पायलेट प्रशिक्षण योजना, एयर होस्टेज प्रशिक्षण योजना, वाहन चालक प्रशिक्षण योजना, नर्सिग प्रशिक्षण योजना आदि के कारण इन वर्गो के बच्चों का आत्मबल बढ़ा है ।

15. मेरी सरकार ने नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवारों के बच्चों की शिक्षा–दीक्षा के लिए 'मुख्य मंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना' लागू करके अपनी संवदेनशीलता और दूरदर्शिता का परिचय दिया है । इस योजना के तहत दंतेवाड़ा में 'आस्था' गुरूकुल में निःशुल्क आवासीय शिक्षा की व्यवस्था की गई है । 'निष्ठा' के तहत राजनांदगांव में अशासकीय संस्था के सहयोग से बच्चों की आवासीय शिक्षा की व्यवस्था की गई है । वहीं 'प्रयास' के तहत दसवीं उत्तीर्ण मेधावी बच्चों को हायर सेकेण्डरी पढ़ाई के साथ अखिल भारतीय स्तर पर मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा हेतु पढ़ाई कराई जा रही है ।

16. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा ऋण पर ब्याज दर में छूट के लिए वांछित आय प्रमाण–पत्र जारी करने की व्यवस्था हेतु नायब तहसीलदार एवं उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है । राज्य के मूल निवासी की प्रदेश के बाहर पढ़ रही संतानों को स्थानीय निवासी प्रमाण –पत्र जारी करने के नियम को भी सरल बनाया गया है ।

17. मेरी सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति में काफी सुधार किया है । राज्य में अब छः शासकीय, दो निजी और एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हो गए हैं । उच्च शिक्षा के आधार में विस्तार करने के कारण राज्य में सकल प्रवेश अनुपात बढ़कर 9 प्रतिशत हो गया है, जिसे आगामी पांच वर्षो में 15 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है ।

18. तकनीकी शिक्षा के विस्तार से क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के कदमों के तहत इस वर्ष गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, जशपुर तथा कोरिया में पॉलीटेक्निक संस्थाएं शुरू की गई हैं । इससे राज्य के सभी जिलों में पॉलीटेक्निक संस्थाएं स्थापित करने का लक्ष्य भी पूर्ण हुआ है । अम्बिकापुर में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोला गया है । आईआईएम की शुरूआत रायपुर में हो गई है । साथ ही नया रायपुर में इसके लिए सुविधाजनक परिसर स्थापित करने हेतु भूमि का आवंटन कर दिया गया है ।

19. विकास को रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए मेरी सरकार ने पूरे राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का जाल बिछाने का फैसला किया है । सिर्फ एक वर्ष में 10 नई आईटीआई खोलकर राज्य में कुल प्रशिक्षण क्षमता में एक हजार 600 सीटों की वृद्धि की जाएगी । छत्तीसगढ़ कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 65 वाकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर का पंजीयन किया जा चुका है । इसके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से भी पांच हजार हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं ।

20. राज्य में खेल का अच्छा वातावरण बनाने और इसे कैरियर निर्माण से जोड़ने की पहल भी मेरी सरकार ने की है । राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा प्रदान करने का वायदा निभाते हुए 'उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा भर्ती नियम' जारी कर इसके तहत नियुक्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । राज्य निर्माण के दस वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य खेल महोत्सव का विकासखंड स्तर से

राज्य स्तर तक सफलतापूर्वक आयोजन किया गया । इस आयोजन में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं ओपन वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया ।

21. निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार कार्यालयों के द्वारा रोजगार मेलों की शुरूआत की गई है। अभी तक पांच जिलों में आयोजित इन रोजगार मेलों में 11 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है। भविष्य में यह मेले हर जिले में प्रतिवर्ष लाए जाएंगे। युवाओं को इस संबंध मे ताजा जानकारी देने के लिए विभागीय वेबसाइट प्रारम्भ की गई है। रोजगार कार्यालयों में ऑन लाइन पंजीयन की व्यवस्था भी की गई है ।

22. चिकित्सा शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की है । विगत वर्ष दो नए नर्सिग कॉलेज कवर्धा तथा रायगढ़ में खोले गए हैं । रायगढ़ में एक नए चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य जारी है । कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत भी एक नया मेडिकल कॉलेज, रायपुर में खोला जाएगा । रायपुर में एम्स की स्थापना के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मेरी सरकार ने आर्थिक सहयोग किया है ।

23. राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए 43 हजार 763 आंगनवाड़ी केन्द्रों को सशक्त बनाया गया है । आंगनवाड़ी केन्द्रों से 18 हजार से अधिक महिला स्व–सहायता समूहों, एक हजार 733 ग्राम पंचायतों और 723 नगरीय निकायों को जोड़कर पौष्टिक आहर प्रदाय की गुणवत्ता बढ़ाई गई है। इसके अलावा 'मातृत्व सहयोग योजना', 'सबला योजना', 'सक्षम योजना' जैसी अन्य योजनाओं का अधिकाधिक लाभ महिलाओं तथा बच्चों को दिया जा रहा है ।

24. विगत दस वर्षों में कुपोषण की दर 61 से घटाकर 52 प्रतिशत तक लाने में सफलता मिली है लेकिन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के तहत सन् 2015 तक इसे 30 प्रतिशत के स्तर पर लाने की चुनौती है । इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए मेरी सरकार ने संस्थागत प्रयासों के साथ व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चलाया है, जिसके तहत गांव–गांव में रैलियां तथा पदयात्राएं आयोजित की जा रही हैं। 21 लाख बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों से पोषण आहार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत गंभीर कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने तथा समर्थ समाज को गोद दिलाने की व्यवस्था भी कारगर रही है ।

25. यह हमारा सौभाग्य है कि स्वामी विवेकांनद के बाल्यकाल का एक बड़ा हिस्सा रायपुर में बीता था। उनसे जुड़ी यादों और संदेशों से नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए मेरी सरकार राज्य में 'स्वामी विवेकानंद विश्व प्रबुद्ध संस्थान' की स्थापना कर रही है। उनके साहित्य के सृजनात्मक अध्ययन हेतु 'स्वामी विवेकानंद शोध पीठ' का गठन भी किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद की 150 वीं जयंती के अवसर पर तीन

वर्षीय समारोह की शुरूआत 12 जनवरी, 2011 से की गई है। सिरपुर, पचराही और मदकूद्वीप में उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। कला–संस्कृति के एकीकृत संकुल 'बहुआयामी संस्कृति संस्थान' के निर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

26. राज्य में ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, प्राकृतिक महत्व के पर्यटन स्थलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ही पर्यटन का विकास सम्भव है । इस दिशा में तेजी लाने के लिए मेरी सरकार ने 'पर्यटन प्रोत्साहन योजना' लागू कर एक ओर जहां निजी निवेशकों की भागीदारी बढ़ाई है, वहीं दूसरी ओर स्वयं भी विभिन्न स्थानों पर कार्य कराए जा रहे हैं । 17 विश्रामगृहों का जीर्णोद्धार किया गया है । हाइवे मोटलों, रिसोर्ट, कॉटेज आदि निर्माण कार्य किए जा रहे हैं ।

27. छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हाथकरघा, रेशम उत्पादन तथा हस्तशिल्प का बड़ा योगदान है। मेरी सरकार ग्रामोद्योग के विकास हेतु अनेक उपाय कर रही है ताकि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। ऐसे प्रयासों से एक वर्ष में 24 हजार बुनकरों को 30.42 करोड़ रूपए के वस्त्र शासन के विभिन्न विभागों में बेचने का अवसर मिला है। एकीकृत हाथकरघा विकास योजना में विभिन्न स्थानों में 10 नए समूहों को मंजूरी दी गई है। चाम्पा तथा छुईखदान में निर्यात योग्य वस्त्रों के उत्पादन तथा उनकी प्रोसेसिंग हेतु केन्द्र खोले जाएंगे। टसर रेशम विकास तथा विस्तार योजना के तहत तीन हजार 729 हेक्टेयर में पुराने पौध रोपण का संधारण तथा 500 हेक्टेयर में नए पौध रोपण का लक्ष्य है। हस्तशिल्पियों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए माना एयरपोर्ट, मुक्तांगन, कोंडागांव, अम्बिकापुर, अहमदाबाद में एम्पोरियम खोले गए हैं।

28. नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार हेतु मेरी सरकार की प्राथमिकता सर्वविदित है। सड़क, प्रकाश, नाली, पेयजल, सामुदायिक भवन, प्रवेश द्वार, खेल मैदान, बस स्टैण्ड, हाट बाजार, सांस्कृतिक भवन, सार्वजनिक प्रसाधन, चौराहों और उद्यानों को सौन्दर्यीकरण, तालाबों का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण आदि सुविधाओं के विकास हेतु प्रदेश के हर नगर में योजनाएं चलाई जा रही है। बिलासपुर में 280 करोड़ रूपए की लागत से भूमिगत नाली का निर्माण कराया जा रहा है। रायपुर में करीब 15 करोड़ रूपए की लागत से 100 सिटी बसें खरीदी जा रही हैं।

29. मेरी सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास का लाभ स्थानीय जनता को दिलाने के लिए स्पष्ट नीति बनाई है, जिसके तहत निजी निवेशकों की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। उन्हें राज्य शासन द्वारा अनुदान, छूट, रियायतों का लाभ तभी मिलेगा, जब वे अकुशल श्रेणी के 90 प्रतिशत, कुशल श्रेणी के 50 प्रतिशत एवं प्रबंधकीय श्रेणी के 33 प्रतिशत रोजगार मूल निवासियों को प्रदान करें ।

30. मेरी सरकार ने विगत वर्ष 2009–10 में तीन हजार 825 किलोमीटर सड़कों तथा 101 वृहद पुलों का निर्माण कराया । विभिन्न विभागों के लिये 406 भवनों का निर्माण पूरा कर लिया गया है । इस वर्ष

854 किलोमीटर सड़कों, 28 बड़े पुलों तथा 159 भवनों का निर्माण पूरा किया जा चुका है । 172 पुलों और 524 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है । मोवा–रायपुर ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा सात ओवरब्रिजों का निर्माण प्रगति पर है । इसी तरह विभिन्न शहरों में पांच बायपास सड़कों का कार्य प्रगति पर है । छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना के अंतर्गत 810 किलोमीटर की 15 पैकेज सड़कों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है तथा 440 किलोमीटर की 6 पैकेज सड़कों का कार्य प्रगति पर है । दो हजार 497 किलोमीटर की 132 ग्रामीण सड़कों को मुख्य जिला मार्ग घोषित किया गया है ताकि उनका समुचित विकास किया जा सके ।

31. राज्य में परिवहन सुविधाओं को आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ दिलाने के लिए मेरी सरकार अनेक कदम उठा रही है। प्रदेश के 15 परिवहन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। शेष एक परिवहन कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। वाहन पंजीयन प्रमाण–पत्र तथा चालक लायसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने की योजना प्रगति पर है। ई–चालान की सुविधा लागू की गई है।

32. मेरी सरकार छत्तीसगढ़ को देश का पावर हब बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। जीरो पावर कट की वजह से छत्तीसगढ़ की देश में एक अलग पहचान बनी है। हमारी विद्युत कंपनियों द्वारा आगामी तीन वर्षों में विद्युत के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण पर 17 हजार करोड़ रूपए का निवेश किया जाएगा। राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनी की दो परियोजनाएं पूर्णता की ओर हैं, जिनसे उत्पादन क्षमता में 1500 मेगावाट की बढ़ोत्तरी होगी। राज्य में विद्युत पारेषण–वितरण प्रणाली के सशक्तीकरण का दौर जारी है, वहीं दो दशकों बाद 400 के.व्ही. पारेषण नेटवर्क की स्थापना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

33. राज्य सरकार के सटीक प्रयासों से राष्ट्रीय औसत 83.80 प्रतिशत के विरूद्ध छत्तीसगढ़ में लगभग 97 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है । राज्य में विभिन्न भवनों की छतों पर जो सौर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं, उनकी सम्मिलित क्षमता सात मेगावाट हो गई है। राज्य के 1400 वनग्राम सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत किए गए हैं और 1150 आदिवासी छात्रावासों में भी सौर ऊर्जा से रोशनी पहुंचाई गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ने ग्रीन पावर तथा अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों के विकास के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। बायोमास से 220 मेगावाट विद्युत उत्पादन होने लगा है, वहीं बायोफ्यूल उत्पादन की दिशा में भी हमारे प्रयास अग्रणी रहे हैं।

34. मेरी सरकार ने साठ सालों में किसानों को मिले पम्प कनेक्शनों के ढाईगुना से अधिक अर्थात् एक लाख 95 हजाए नए पम्प कनेक्शन सिर्फ सात सालों में दिए हैं । किसानों को उनके पांच हार्स पावर तक के पम्पों को प्रति वर्ष छह हजार यूनिट बिजली निःशुल्क दी जा रही है । ऐसे दो लाख 37 हजार पम्पों को निःशुल्क बिजली देने का लक्ष्य है । राज्य में करीब 13 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली दी जा रही है ।

35. मेरी सरकार ने राज्य में आवास क्रांति को सशक्त बनाने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना हाथ में ली है । प्राथमिकता के आधार पर जिला तथा ब्लाक मुख्यालयों, छोटे शहरों, बड़े गांवों, औद्योगिक क्षेत्र, कुटीर उद्योग–क्लस्टर क्षेत्र तथा उसके आस–पास 'विकास नगर योजना' प्रारम्भ की जा रही है । इसके अंतर्गत समस्त बुनियादी अधोसंरचना का विकास किया जाएगा । तीन वर्षों में एक लाख आवास बनाए जाएंगे, जो मुख्यतः निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लिए होंगे ।

36. मेरी सरकार ने राज्य में वनों की अधिकता से विकास कार्य बाधित होने की कठिनाइयों के बीच भी स्थानीय विकास का रास्ता निकाला है । सिंचाई, खनिज, विद्युत जैसी विभिन्न 243 परियोजनाओं में वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति केन्द्र से प्राप्त की गई हे संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत वन सुरक्षा समितियों को उत्पादित वनोपज में हिस्सेदारी के रूप में 22.19 करोड़ रूपए का भुगतान बीते एक वर्ष में किया गया है । 425 वन ग्रामों के समग्र विकास हतु 100 करोड़ रूपए की लागत से 9 हजार से अधिक कार्य स्वीकृत कराए गए हैं, जिनमें से करीब 7 हजार 700 पूरे किए जा चुके हैं । कैम्पा फण्ड हेतु मिली 257 करोड़ रूपए की राशि का उपयोग क्षतिपूरक वनारोपण, वन सुरक्षा, वन उत्पादकता वृद्धि जैसे अनेक कार्यों में किया जा रहा है ।

37. मेरी सरकार ने लघु वनोपजों से जीवन–यापन करने वाले तेन्दूपत्ता, सालबीज संग्राहकों तथा लाख उत्पादकों को आमदनी बढ़ाने के नए अवसर दिए हैं । विगत एक वर्ष में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 108 करोड़ रूपए की मजदूरी तथा 92 करोड़ रूपए का बोनस दिया गया । साल–बीज संग्राहकों को करीब 7 करोड़ रूपए संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में दिए गए । विगत वर्ष प्रदेश लगभग 5 हजार मीट्रिक टन लाख उत्पादन हुआ, जो देश में सर्वाधिक है । मेरी सरकार तेन्दूपत्ता संग्राहकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए 'जनश्री बीमा योजना' और समूह बीमा योजना को यथावत जारी रखेगी । अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु विशेष प्रयास करेगी ।

38. पिछड़े अचंलों में बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई सोच और नई रणनीति आवश्यक होती है। मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए तीन प्राधिकरण गठित करने की पहल को अच्छे परिणामों तक पहुंचाया है। इस कड़ी में 'बस्तर विकास समूह' गठित करने से स्थानीय विकास के कार्यों को नई गति मिलेगी।

39. गांवों के विकास के लिए मेरी सरकार ने त्रि–स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की रणनीति अपनाई है । उन्हें पंचायतों के कामकाज में दक्ष बनाने के लिए इस वर्ष एक लाख 30 हजार से अधिक निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, शासकीय अमले तथा अन्य लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। पंचायतों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए 'प्रिया साफ्ट लेखा प्रणाली' लागू करने हेतु विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है ।

40. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक 17 हजार 780 किलोमीटर लम्बी तीन हजार 876 सड़कें तथा 20 हजार 900 पुल–पुलियों का निर्माण पूरा किया जा चुका है । इस तरह राज्य की आठ हजार 58 बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा चुका है । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का भरपूर लाभ ग्रामीण जनता को दिलाने के लिए न केवल समुचित व्यवस्थाएं की गई बल्कि कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण भी पूर्ण कराया गया है । चालू वर्ष में मांग के आधार पर 21 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 790 लाख मानव दिवस सृजित किए गए ।

41. राज्य में खनिज सम्पदा पर आधारित उद्योगों की स्थापना से स्थानीय लोगों की प्रगति का सीधा रिश्ता बने इस बाबत् मेरी सरकार ने पूरा ध्यान रखा है । राज्य में खनन करने वाली सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वे अपने शुद्ध लाभ का न सिर्फ 10 प्रतिशत हिस्सा सामुदायिक विकास में खर्च करें बल्कि इस 20 प्रतिशत तक बढ़ाएं ।

42. राज्य में कानून–व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए मेरी सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं। नक्सलियों द्वारा बढ़ाए गए दबाव के बावजूद राज्य के सभी क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ने का एक प्रमुख कारण सुरक्षा के प्रति आम जनता का विश्वास भी है । प्रति वर्ष पुलिस बलों में 3–4 हजार नवीन पदों पर भर्ती का क्रम जारी है । वर्ष 2010 में तीन हजार 129 नवीन पद सृजित किए गए, जिसके कारण राज्य का स्वीकृत बल बढ़कर 51 हजार 909 हो गया है । विशेष तौर पर नक्सली गतिविधियों पर अंकुश के लिए चौदहवीं भारत रक्षित वाहिनी के गठन हेतु 1007 नए पदों का निर्माण किया गया है, वहीं तीन हजार विशेष पुलिस अधिकारियों के नवीन पद भी निर्मित किए गए हैं ।

43. पुलिस बलों में प्रशिक्षण तथा दक्षता बढ़ाने के लिए एसटीएफ, एटीएस, सीआईएटी जैसी संस्थाएं प्रारम्भ की गई हैं । सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने हेतु पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन बनाने की पहल की गई है।

44. मेरी सरकार ने छोटे–बड़े शहरों से लेकर दूरस्थ गांवों तक के बीच इलेक्ट्रॉनिक सम्पर्क कायम करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लिया है । हाईब्रिड नेटवर्क, लीज्ड लाइन, वायमेक्स, वी–सेट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का शासन–प्रशासन के लिए उपयोग करने में भी छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य बना है । शहरों की तरह चॉइस परियोजना का लाभ गांवों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं । इसके तहत राज्य मुख्यालय से प्रदेश के तीन हजार 500 कार्यालयों को जोड़ा जा रहा है तथा गांवों में बड़े पैमाने पर चॉइस जैसे केन्द्र खोले जा रहे हैं ।

45. छत्तीसगढ़ ने विगत दस वर्षों में अपनी क्षमता से देश तथा दुनिया को आकर्षित किया है । इसके साथ ही राज्य में विश्व स्तरीय अधोसंरचना की जरूरत भी महसूस की गई है, जिसमें प्रदेश की सुनियोजित और अत्याधुनिक राजधानी भी शामिल है । इसलिए मेरी सरकार ने वर्तमान रायपुर के विकास पर भरपूर

ध्यान देते हुए 'नया रायपुर' के विकास में भी तेजी लाई है । 'नया रायपुर' छत्तीसगढ़ की संस्कृति और क्षमताओं की मिसाल बनेगा, जिसके प्रशासनिक परिसर का कार्य आगामी एक वर्ष में पूर्ण करने हेतु तेजी से कार्य किया जा रहा है ।

46. चुनौतियों से जूझने और विजयी होने की जो क्षमता छत्तीसगढ़ में है, उससे मैं भली–भांति परिचित हूं । मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें भी छत्तीसगढ़ जीतेगा । आपकी यह विजय राज्य के विकास की संभावनाओं पर और भी सुनहरे पंख लगाएगी । आप सबके प्रयासों से राज्य और यहां की जनता दिन दूनी–रात चौगुनी तरक्की करे, इसके लिए मेरी कोटिशः शुभकामनाएं ।

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़